विश्वनाथ झुनझुनवाला

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

अप्रैल 16, 2004

[एस. राजेंद्र बाबू और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपतिगण]

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948:

धाराये 2 (एए) और 28-ए (1) - "व्यवसाय" - प्रपत्र-31 में घोषणा के संबंध में कोयले का आयात - फर्म अपने स्वंय के खाते के साथ साथ जॉब वर्क के आधार पर तेल के शोधन में लगी हुई है - नौकरी के काम के लिए फॉर्म-31 पर आयातित कोयले का उपयोग करने की अनुमति नहीं है - अभिनिर्धारित, व्यवसाय की अवधारणा प्रसंस्करण सामग्री को बाहर नहीं करेगी - कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए आयातित कोयला अधिनियम की धारा 2(एए) के तहत "व्यवसाय" की परिभाषा में शामिल किया गया है - फर्म की गतिविधियों में नौकरी का काम शामिल है जिसमें कोयले की खरीद शामिल है और यह "व्यवसाय"की परिभाषा में बहिष्करणीय खंड से बाहर है।

अपीलकर्ता-फर्म अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ नौकरी के आधार पर भी तेल शोधन में लगी हुई थी। इस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता सड़क मार्ग से केंद्रीय कोयला क्षेत्रों से कोयले का आयात कर रहा था। जब अपीलार्थी ने यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित 1300 प्रपत्र-31 जारी करने के लिए आवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 2, सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) ने एक नोटिस जारी किया जिसमें अपीलार्थी को कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि फर्म पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि जो कोयला फार्म-31 पर आयात किया जा रहा था का उपयोग

नौकरी के काम के लिए किया जा रहा था, जबकि इसका उपयोग अपने व्यवसाय के लिए किया जाना चाहिए। अपीलार्थी को निर्देश दिया गया था कि वह नौकरी के लिए फॉर्म 31 पर आयातित कोयले का उपयोग न करे। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा नौकरी के काम के लिए आयात किया जाने वाला कोयला उसके व्यवसाय के संबंध में नहीं था, इसलिए उसके लिए फॉर्म 31 जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए अपीलें हैं।

अपीलों को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 .स्वीकृत रूप से अपीलकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से कायला खरीदा और आयात किया जाता है, और इसलिये, आवश्यक रूप से इसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री शामिल है, यदि नहीं, तो कुछ भी कम। परिभाषा के अनुसार "व्यवसाय" की अवधारणा में प्रसंस्करण सामग्री को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि अपीलकर्ता कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिये उसके द्वारा आयातित कोयले का उपयोग करता है और ऐसी गतिविधि को धारा 2 (ए. ए.) यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत "व्यवसाय" की परिभाषा में भी शामिल किया गया है। [299 - ई-एच]

गणेश प्रसाद दीक्षित बनाम बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, [1969] 1 एस. सी. सी. 492 और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एच. अब्दुल बख्शी और ब्रदर्स, 15 एसटीसी 644, पर भरोसा व्यक्त किया

1.2 . जब अपीलार्थी की गतिविधियों में अनिवार्य रूप से, उसके द्वारा किया गया नौकरी का काम शामिल होगा और वह यह काम कोयले की खरीद के बाद के अलावा नहीं कर सकता है, उसकी गतिविधियों को भले ही केवल सेवा की प्रकृति में एक कहा जाए, उसमें कोयले की खरीद शामिल होगी और उस स्थिति में यह "व्यवसाय" की परिभाषा में बहिष्करण खंड से बाहर है। [300 - ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 164/1997

(सी.एम.डब्लू.पी. संख्या 1065/1994 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.5.96 से।)

साथ में

सी. ए. नंबर 165-166 / 1997

सुनील गुप्ता और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सी. ए. नं. 64/97 में अपीलार्थीगण के लिये।

मैसर्स जे.बी. दादाचंजी एंड कंपनी (एनपी) अपीलार्थीगण के लिये सी.ए. नंबर 165-166/1997 में ।

आर. सी. वर्मा, मुकेश वर्मा और मनीष शंकर, प्रतिवादीगणो के लिए।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। शुरुआत में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि विद्वान वकील उन संशोधनों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं जो प्रश्न क़ानूनों में लागू किए गए हैं। हम अपने सामने रखी गई सामग्री और उनके द्वारा लिए गए रुख के आधार पर आगे बढ़ने के लिए विवश हैं।

हमारे समक्ष अपीलार्थी एक साझेदारी फर्म है जो उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम') और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानो के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत है। फर्म अपने स्वंय के खर्चे पर और जॉब वर्क के आधार पर तेल के शोधन में लगी हुई है। इस उद्देश्य के लिए फर्म को भाप कोयला की बडी मात्रा में परिष्कृत तेल के निर्माण के लिये ईंधन के रूप में उपयोग की आवश्यकता थी। केन्द्रीय कोयला क्षेत्र, रांची से वाराणसी तक सड़क मार्ग से कोयला लाने के लिए, जहाँ अपीलार्थी का कारखाना स्थित है, अपीलार्थी को अधिनियम

के तहत निर्धारित फॉर्म 31 की आवश्यकता थी और सहायक आयुक्त (निर्धारण) । व्यापार कर वाराणसी, यहां प्रतिवादी संख्या 2; से 1300 प्रपत्र 31 जारी करने के लिए अनुरोध किया, जिन्होंने प्रपत्र 31 जारी करने के बजाय अधिनियम की धारा 15-ए (1) (आर) के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें अपीलार्थी से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि कोयला, जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र 31 पर आयात किया जा रहा था, का उपयोग नौकरी के काम पर किया जा रहा था जबकि इसका उपयोग अपने व्यवसाय के लिए किया जाना था। अपीलार्थी ने उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दिया और एक आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी को नौकरी के काम के लिए फॉर्म 31 पर आयातित कोयले का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 28-एक उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि एक आयातक जो राज्य के बाहर किसी भी स्थान से राज्य मे लाने, आयात करने या अन्यथा प्रापत करने का इरादा रखता है, अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी किसी भी वस्तु अपने व्यवसाय के संबंध में इस प्रावधान के तहत प्रदान की गई ऐसी मात्रा या माप या ऐसे मूल्य में, वह फार्म 31 में निर्धारित घोषण प्राप्त करेगा और यदि वह व्यवसाय के संबंध में अन्यथा ऐसे सामान लाने, आयात करने या प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह कर सकता है, इसी तरह, प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रपत्र, यानि फार्म 30 प्राप्त कर सकता है। न्यायालय के समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि कोयले की बिक्री और खरीद के लेन-देन कर के अधीन थे और अपीलार्थी धारा 28-ए के तहत उल्लिखित सीमाओं से अधिक कोयले का आयात कर रहा था और इसलिए, अपीलार्थी को फॉर्म 31 प्राप्त करना चाहिए था यदि वह अपने व्यवसाय के संबंध में कोयला लाने या आयात करने का

इरादा रखता है और यदि वह अपने व्यवसाय के संबंध में कोयले को लाने या आयात करने का इरादा रखता है, तो वह फॉर्म 32 प्राप्त कर सकता है।

प्रतिवादियों द्वारा न्यायालय के समक्ष स्थापित मामला यह है कि अपीलार्थी द्वारा आयातित कोयला न केवल उसके व्यवसाय के संबंध में है, बल्कि नौकरी के लिए भी है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने "व्यवसाय" की परिभाषा को दोहराते हुए कहा कि अपीलकर्ता परिष्कृत तेल के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है और इसके अलावा, अपीलकर्ता नौकरी के आधार पर तेल को भी परिष्कृत करता है; कि "व्यवसाय" शब्द में नौकरी का काम शामिल नहीं होगा, यानी एक ऐसी गतिविधि जो केवल सेवा की प्रकृति में है जिसमें वस्तुओं की खरीद या बिक्री शामिल नहीं है; कि, इसी तरह, अपीलकर्ता द्वारा नौकरी के काम पर उपयोग किए जाने के लिए आयात किया जाने वाला कोयला उसके व्यवसाय के संबंध में नहीं है और इसलिए फॉर्म संख्या 31 इसके लिये जारी नहीं किया जा सकता है।

यह उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ है कि अपीलकर्ता अपील में है।

"व्यवसाय" शब्द को अधिनियम की धारा 2 (एए) के तहत परिभाषित किया गया है और इस प्रकार पठनीय है :

"माल खरीदने या बेचने के व्यवसाय के संबंध में "व्यवसाय" में शामिल हैं :

(I) कोई भी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में कोई साहसिक कार्य या चिंता, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, साहसिक कार्य या चिंता लाभ कमाने के उददेश्य से किया जाता है या नहीं ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, साहसिक कार्य या संस्था से कोई लाभ अर्जित होता है, संयत्र, मशीनरी, कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री, खाली सामान, उपभोज्य भंडार, अपशिष्ट या उप-उत्पाद, या समान प्रकृति के किसी भी अन्य सामान या किसी

अनुपयोगी या अप्रचित या छोडी गई मशीनरी या किसी को खरीदने, बेचने या आपूत्रि करने का कोई भी लेनदेन उसके पुर्जे या सहायक उपकरण या कोई अपशिष्ट या स्क्रैप या उनमें से कोई (या कोई अन्य लेनदेन) जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निमार्ण, साहसिक कार्य या चिंता से संबंधित है या उसके साथ जुडा हुआ है या उसका परिणाम है; लेकिन इसमें केवल सेवा या पेशे की प्रकृति की कोई गतिविधि शामिल नहीं है जिसमें वस्तुओं की खरीद या बिक्री शामिल नहीं है।"

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि "व्यवसाय" शब्द में केवल सेवा या पेशे की प्रकृति की कोई गतिविधि शामिल नहीं होगी जिसमें माल की खरीद या बिक्री शामिल नहीं है। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से अपीलार्थी द्वारा कोयले की खरीद और आयात किया जाता है और इसलिए, आवश्यक रूप से इसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री शामिल है, यदि नहीं, तो कुछ भी कम। परिभाषा के अनुसार "व्यवसाय" की अवधारणा में "प्रसंस्करण सामग्री" को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि अपीलकर्ता कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए अपने द्वारा आयातित कोयले का उपयोग करता है और ऐसी गतिविधि को "व्यवसाय" की परिभाषा में भी शामिल किया गया है।

गणेश प्रसाद दीक्षित बनाम बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, [1969] 1 एससीसी 492, में इस न्यायालय ने "व्यवसाय" अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एच. अब्दुल बख्शी और ब्रदर्स , 15 एसटीसी 644 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया गया:

> "व्यापारी बनने के लिये एक व्यक्ति को माल खरीदने या बेचने या आपूत्रि करने के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिये। हालांकि व्यवसाय शब्द व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अनिश्चितकालीन का

शब्द है। कर कानूनो में इसकाउपयोग एक व्यवसाय या पेशे के अर्थ में किया जाता है जो किसी व्यक्ति का समय, ध्यान और श्रम लेता है, आम तौर पर लाभ कमाने के उददेश्य से। किसी गतिविधि को व्यवसाय मानने के लिए लेन देन का एक क्रम होना चाहिये, या तो वास्तव में जारी रखा जाना चाहिये या लभ के उददेश्य से जारी रखा जाना चाहिये, न कि खेल या आनंद के लिये। लेकिन व्यापारी होने के नाते एक व्यक्ति को एक ही वस्तु खरीदने, बेचने और आपूर्ति करने की गतिविधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिये, यानि लाभ के उददेश्य के बिना, किसी व्यक्ति को अधिनियम के अर्थ के तहत डीलर नहीं बनाया जायेगा, बल्कि वह व्यक्ति जो अपने व्यापार के दौरान उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु का उपभोग करता है, या बिक्री के लिये किसी अन्य वस्तु के निर्माण में उपयोग करता है, एक डीलर के रूप में माना जायेगा। विधायिका ने किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तु की बिक्री को ही उसे व्यापारी मानने की शर्त नहीं बना दी है; परिभाषा में केवल यह आवश्यक है कि नियम 5 (2) में उल्लिखित वस्तु की खरीद व्यवसाय के दौरान होनी चाहिये, यानि खरीद और निपटान की एकीकृत गतिविधि से लाभ कमाने की दृष्टि से बिक्री या उपयोग के लिये होनी चाहिये। वस्तु को स्वंय किसी अन्य बिक्री योग्य वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है,या इसका उपयोग एक घटक के रूप में या ऐसी बिक्री योग्य वस्तु के उत्पादन के लिये विनिर्माण प्रक्रिया में सहायता के लिये किया जा सकता है।"

जब अपीलार्थी की गतिविधियों में अनिवार्य रूप से उसके द्वारा किया गया नौकरी का काम शामिल होगा और वह कोयले की खरीद के अलावा यह कार्य नही कर सकता है, तो उसकी गतिविधियो को भले ही केवल सेवा की प्रकृति में से एक कहा गया हो, इसमें कोयले की खरीद शामिल होगी और उस स्थिति में यह "व्यवसाय" की परिभाषा में बहिष्करण खंड से बाहर आता है।

मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है और उसे अपास्त किया जाता है और बदले में सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी अपास्त किया जाता है। अपीले स्वीकार की जाती है।

आर. पी.

अपीले स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।